दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

क्रमाँक : एफ-18/पी.सी./ए.क्यू.सी.75/ 81-23 दिनाँक: 16/3/18

विषय :- श्री दिनेश मोहनिया, विधायक द्वारा पूछे गये विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 75 दिनांक20.03.2018 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
(क)विगत पांच वर्षो में डीयूएसआईबी ने डब्ल्यू सी सीट वाले कितने शौचालय परिसरों का निर्माण किया है व इनके निर्माण में कुल कितना व्यय हुआ है;	विगत पांच वर्षो में डीयूएसआईबी द्वारा 245 शौचालय परिसरों का निर्माण किया गया। शौचालयों के निर्माण व उन्नयन में कुल 140.50 करोड़ रूपये व्यय किये गये।
(ख) डीयूएसआईबी के अंतर्गत कुल शौचालय परिसरों में से कितने इसके गठन अर्थात् 2010 के पहले से थे और कितने बाद में बनाए गए, वर्षवार ब्यौरा क्या है;	डीयूएसआईबी के अंतर्गत आने वाले 620 शौचालय परिसरों में से 183 शौचालय परिसर 2010 से पहले के थे व 245 शौचालय परिसर 2010 के बाद में बनाये गये। इसके अतिरिक्त 192 शौचालय परिसर दिल्ली नगर निगम से समय-समय पर अधिगृहीत किये गये है।
(ग)वर्ष 2010के बाद से इन सभी शौचालय परिसरों की देखरेख पर होने बाले खर्च का ब्यौरा क्या है;	बर्ष 2010 के बाद से 2016-2017 तक पे एण्ड यूज योजना के अन्तर्गत कुल निर्माण व रखरखाव पर 146.52 करोड़ रूपये व्यय हुआ है।
(घ)दिल्ली नगर निगम से अधिगृहीत शौचालय परिसरों की सूची तथा ऐसे सभी शौचालय परिसरों पर होने बाले बिजली खर्च का ब्योरा क्या है;	दिल्ली नगर निगम से अधिगृहीत शौचालय परिसरों की सूची संलग्न है। दिल्ली नगर निगम अधिगृहीत शौचालय परिसरों में रख-रखाव एजेंसियों द्वारा विजली क्नैक्शन स्वयं लिए गये एंव विजली का खर्च रख-रखाव एजेंशियों द्वारा दिया गया।
(ङ)जिन अधिकारियों ने दिल्ली नगर निगम से शौचालय परिसरों को बिजली खपत राशि के भुगतान के बकाए के साथ ही अधिगृहीत किया उनकी सूची क्या है;	यह एक पोलिसी निर्णय था, अतः इसमें किसी अधिकारी का व्ययक्ति गत निर्णय नहीं है।
(च)क्या यह सत्य है कि आज की तारीख में कम से कम 150 शौचालय परिसर ऐसे हैं जिनमें वैध बिजली कनेक्शन नहीं है और वहां	टेन्डर की शर्तो के अनुसार बिजली का इन्तजाम व कनेक्शन रखरखाव एजेन्सी के द्वारा लिया जाता है। आज की तारीख में 67 शौचालयों में कनेक्शन के लिए आवेदन

मुख्य लाइन अवैध बिजली लेकर काम चलाया जा रहा है;	किया हुआ है। जिनमें स्थानीय व्यवस्था की गयी है। DISCOM के द्वारा MCD के समय के लम्बित बकाया राशी के कारण कनेक्शन देने से मना करने के कारण कनेक्शन लम्बित है। अब माननीय मंत्री (शहरी विकास) की स्वीकृती के बाद MCD की बकाया राशि को डूसिब के द्वारा देने के बाद DISCOM के अधिकारी कनेक्शन देने के लिए तैयार हो गये है और उम्मीद है की एक महीने में सभी शौचालयों में मीटर लग जाएगा।
(छ)ऐसी खतरनाक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के नाम क्या हैं;	उपरोक्त
(ज)पूर्वनिर्मित शौचालयों, मोबाइल टॉयलेट वैनों, पोर्टेबल क्युबिकल शौचालयों आदि सहित सभी शौचालयों तथा डीयूएसआईबी की सभी परिसंपत्तियों में बिजली कनेक्शन की वर्तमान स्थिति क्या है;	DUSIB के टॉयलेटस में इलेक्ट्रिक कनेक्शन की जिम्मेदारी ओ. एण्ड एम. एजेन्सी की है, कुछ कॉम्पलेक्श में डीस्कोम ने कनेक्शन देने से मना किया था क्योकि MCD के समय के ड्यूज पेन्डिंग थे। अब माननीय मंत्री (शहरी विकास) के द्वारा MCD के ड्यूज देने की स्वीकृति के बाद डूसिब ने MCD के पेन्डिंग ड्यूज दे दिये है। व अब डीस्कोम ने कनेक्शन देने के लिए तैयारी कर ली है। DUSIB के 620 कॉम्पलेक्स में से 453 में इलेक्ट्रीक मीटर लगे हुये है व 67 में अप्लाई किया हुआ है और 100 एम.टी.वी. व पोर्टेबल में इलेक्ट्रिक कनेक्शन की जरूरत नहीं है।
(झ)कितने शौचालय दिव्यांगों के अनुकूल हैं और कितने शौचालय ऐसे हैं जो दिव्यांगों के अनुकूल नहीं हैं; और	372 शौचालय दिव्यांग अनुकूल है, तथा 248 शौचालय दिव्यांग अनुकूल नहीं है जिनमें ऐसा प्रावधान करने के प्रयास जारी है।
(ट) उक्त शौचालयों का पिछले पांच वर्ष का शौचालय परिसरवार ब्यौरा क्या है?	प्रश्न स्पष्ट नहीं है।

यह उत्तर सक्षम आधिकारी की पूर्व अनुमति से प्रेषित किया जाता है।

उप निदेशक (ससंद प्रकोष्ट)

उप सचिव (श .वि.), दिल्ली सचिवालय,दिल्ली सरकार